

गोवा में आर्थिक और वित्तीय गतिविधियाँ *

दीपक मोहंती

मैं गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा श्री मंगरीश पाइ रायकर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे लब्धप्रतिष्ठ लोगों की इस सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। चूँकि गोवा इस समय अपनी मुक्ति का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, मैंने सोचा कि यह अवसर इस राज्य की हाल की आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख करने का उपयुक्त समय है।

गोवा का सुरम्य राज्य भारतीय राज्यों के संघ का 25वाँ राज्य है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.11 प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ है और इसकी आबादी राष्ट्रीय आबादी का 0.12 प्रतिशत है। तथापि, अखिल भारतीय निवल देशी उत्पाद (एनडीपी) में इसका 0.4 प्रतिशत का बड़ा हिस्सा है। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि क्यों गोवा भारत का सबसे धनी राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का लगभग तीन गुणा है। इसकी आधारभूत संरचना के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने इसे सर्वोत्तम राज्य का दर्जा दिया था। जीवन की सर्वोत्तम गुणवत्ता की दृष्टि से भी इसे आबादी पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत के शीर्षस्थ राज्यों में गिना गया। भारत की मानव विकास रिपोर्ट 2011 ने देश में समग्र मानव विकास के संदर्भ में गोवा को चौथे स्थान पर रखा। इसके प्राकृतिक दृश्य की हरियाली, भौगोलिक और पारिस्थिक विविधता तथा सांस्कृतिक समृद्धि गोवा को यात्रियों का स्वर्ग बना देते हैं। इन उपलब्धियों के होते हुए भी गोवा अनेक प्रकार की विकासात्मक चुनौतियों का सामना करता है जिनमें बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र शामिल हैं।

टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सुचारु रूप से कार्य करने वाली एक वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। जबकि रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के विकास के कार्य में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, इसने हाल के वर्षों में औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की व्याप्ति को बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन के संवर्धन के प्रयास तेज कर दिये हैं ताकि हमारे समाज के लोग सुखी और प्रसन्न हों। इस संबंध में रिजर्व बैंक राज्य में बैंकिंग सुविधाओं की

पहुँच का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास करता रहा है। इस पृष्ठभूमि में मैं इस राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय संरचना की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ और रिजर्व बैंक द्वारा किये गये विभिन्न वित्तीय समावेशन प्रयासों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आगे मैं कुछ नीतिगत चुनौतियों को भी सामने रखना चाहूँगा।

समष्टिआर्थिक संरचना

मैं 2000 के दशक में समष्टिआर्थिक प्रवृत्तियों पर चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि निवल राज्य देशी उत्पाद (एनएसडीपी) के संबंध में जानकारी वर्ष 2009-10 तक उपलब्ध है। पिछले दशक का लक्षण था अखिल भारतीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि में तेजी के रुख का रहना। जबकि अखिल भारतीय एनडीपी 2000 के दशक में 7.1 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर बढ़ा, गोवा का निवल राज्य देशी उत्पाद (एनएसडीपी) 6.6 प्रतिशत की दर पर कुछ कम बढ़ा। लेकिन 2000 के दशक के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण वृद्धि वेग दिखाई पड़ा। एनएसडीपी वृद्धि जो 2000 के दशक के प्रथमार्ध में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, वह दुगुनी हो कर 2000 के दशक के उत्तरार्ध में 8.8 प्रतिशत हो गयी। महत्वपूर्ण रूप से गोवा ने वर्ष 2009-10 में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि-दर दर्ज की - जो दशक की सबसे ऊँची दर थी। इस दर पर गोवा वर्ष 2009-10 में सबसे तेजी से बढ़ने वाले शीर्षस्थ पाँच राज्यों में से एक था जबकि अखिल भारतीय वृद्धि-दर 7.6 प्रतिशत थी। उच्च वृद्धि-दर दर्ज करने पर गोवा के लिए वृद्धि की इस गति को इस दशक में बनाये रखने की चुनौती होगी (सारणी 1)।

2000 के दशक के उत्तरार्ध में वृद्धि-वेग का प्रतिबिंब उच्च प्रति व्यक्ति आय में भी परिलक्षित हुआ। वर्ष 2009-10 में गोवा की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय (2004-05 की कीमतों पर) 98,807 रुपये पर काफी ऊँची थी जबकि अखिल भारतीय औसत 33,731 रुपये था। अमरीकी डॉलर में, गोवा की प्रति व्यक्ति आय, जो वर्ष 2000-01 में प्रति व्यक्ति 1,217 अमरीकी डॉलर थी, वह वर्ष 2009-10 में बढ़कर 2,910 अमरीकी डॉलर हो गयी। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में गोवा भारत का सबसे धनी राज्य है (सारणी 2)।

*31 अक्टूबर 2011 को गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण। डॉ. पी.के. नायक और श्री सूरज. एस द्वारा दी गयी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

1 अन्य राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और गुजरात।

सारणी 1: क्षेत्रीय आय-पैटर्न

क्षेत्र	वृद्धि-दर * (%)				एनएसडीपी में अनुपातिक हिस्सा (%)	
	2000-05	2005-10	2000-10	2009-10	2000-01	2009-10
कृषि	0.1 (1.5)	-0.3 (2.7)	-0.1 (2.1)	-3.8 (-0.2)	8.7 (23.6)	4.7 (15.2)
उद्योग	7.4 (5.7)	6.8 (7.9)	7.1 (6.8)	5.3 (7.0)	32.9 (17.4)	31.0 (16.5)
सेवा	3.8 (7.7)	11.0 (10.2)	7.4 (8.9)	18.1 (9.6)	58.3 (58.7)	64.3 (68.3)
निर्माण	2.6	6.3	4.5	6.4	13.4	10.3
परिवहन और संचार	15.8	22.7	19.3	43.8	9.3	23.1
बैंकिंग और बीमा	7.4	15.8	11.6	12.2	4.8	8.4
राज्य देशी उत्पाद	4.5	8.8	6.6	12.6	100	100
	(5.8)	(8.4)	(7.1)	(7.6)		

* एनएसडीपी गोवा के लिए और एनडीपी भारत के लिए स्थिर कीमतों पर (2004-05)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गये आँकड़े अखिल भारतीय एनडीपी से संबंध रखते हैं।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

वर्ष 2000-01 और 2009-10 के बीच एनएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना के संदर्भ में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों का हिस्सा तेजी से कम हुआ, जबकि उद्योग का हिस्सा स्थिर बना रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृषि-क्षेत्र में दशक के दौरान नगण्य वृद्धि देखी गयी, जो गतिहीन कृषि-उत्पादन, मछलियाँ पकड़ने के काम में गिरावट और वन-क्षेत्र के गिरते उत्पादन में प्रतिबिंबित होता है। तथापि, उद्योग का हिस्सा राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक था, जिसने गोवा को औद्योगिक राज्य बना दिया। सेवा-क्षेत्र की वृद्धि में हाल ही में तेजी दिखाई पड़ने लगी है जो अधिकतम परिवहन, संचार और वित्त द्वारा प्रेरित है। फलतः एनएसडीपी में सेवा-क्षेत्र का हिस्सा तेज गति से बढ़ा जबकि कृषि का कम हुआ। उद्योग का हिस्सा लगभग अपरिवर्तित बना रहा (सारणी 1)।

ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा है कि गोवा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम पर्यटन और खनन द्वारा किया जाता है लेकिन इसके विपरीत प्रत्येक क्षेत्र के अलग-अलग हिस्से का विश्लेषण करने से पता चलता है कि विनिर्माण और संचार क्षेत्रों ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में काफी योगदान किया है (चार्ट 1)। उत्तम आधारभूत संरचनाएँ जिनमें केंद्रीय स्थान पर विमानपत्तन, सागरपत्तन, उत्कृष्ट सड़क नेटवर्क से संयोजकता और अन्य आधारभूत संरचनाएँ यथा, कंटेनर फ्रेट स्टेशन ने औद्योगिकरण की सहायता की है। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा अपनायी गयी औद्योगिक नीति, खास कर औद्योगिक समूहों/ संपदाओं का विकास किये जाने से उद्योग को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक

कार्यकलापों में सम्मिलित हैं, फार्मास्युटिकल्स, विद्युत और ऑटोमोबाइल उपकरण। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रतियोगितात्मकता संस्थान (हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रणनीति एवं प्रतियोगितात्मकता संस्थान के वैश्विक नेटवर्क का एक भारतीय अंश) द्वारा की गयी हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार गोवा देश में उच्च आय तथा उपभोग पैटर्न एवं अनुकूल जनानिकी के साथ सर्वाधिक प्रतियोगी राज्य बन कर उभरा है।

मुद्रास्फीति संबंधी चुनौतियाँ

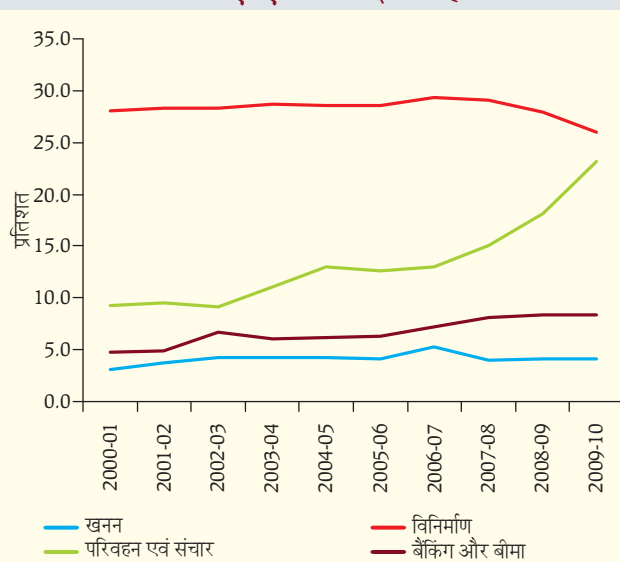
मुद्रास्फीति एक प्रमुख चिंता का विषय है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी। जबकि हम मौद्रिक नीति को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) मुद्रास्फीति के संबंध में स्पष्ट करते हैं, हम सकल और भिन्न-भिन्न स्तरों, दोनों पर उपलब्ध मूल्य सूचकांकों को ध्यान में रखते हैं। हम क्षेत्रीय स्तर पर भी मुद्रास्फीति संकेतकों के प्रति

सारणी 2: प्रति व्यक्ति आय

	2000-01	2004-05	2009-10
गोवा (रुपये में)*	57,447	76,426	132,719
अखिल भारत (रुपये में)*	17,516	24,143	46,492
गोवा (अमरीकी डालर में)	1,217	1,733	2,902
अखिल भारत (अमरीकी डालर में)	371	547	1,016

*वर्तमान कीमतों पर

चार्ट 1: एनएसडीपी में क्षेत्रीय हिस्सा



संवेदनशील होते हैं। 25 अक्टूबर 2011 की अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में हमने 13वीं बार नीति रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ा कर 8.5 प्रतिशत कर दिया ताकि मुद्रास्फीति को रोका जा सके और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम लगायी जा सके। तथापि इस बात की आवश्यकता है कि मुद्रास्फीति की समस्या के माँग और आपूर्ति, दोनों पक्षों पर ध्यान देने के लिए एकजुट प्रयास किया जाये। आपूर्ति पक्ष के संबंध में राज्य सरकारों को आधारभूत संरचना को मजबूत करने और उत्पादकता, विशेष रूप से कृषि में, बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

गोवा में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जिसे औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आइडब्ल्यू) द्वारा मापा जाता है, 2000 के दशक के प्रथमार्ध में लगभग राष्ट्रीय औसत के समान न्यून थी। तथापि जैसे ही 2000 के दशक के उत्तरार्ध में वृद्धि ने रफ्तार पकड़ी, वैसे ही मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी और वह राष्ट्रीय औसत से ऊँची हो गयी। वर्ष 2010-11 में यह दहाई अंकों में थी हालाँकि अगस्त 2011 में इसमें नरमी आ कर यह 9.0 प्रतिशत हो गयी (सारणी 3)। चूँकि खाद्यान्न का काफी भार उपभोक्ता मूल्य समूह में होता है, यह मुद्रास्फीति का प्राथमिक स्रोत होता है। गोवा अनेक प्रकार की खाद्य-वस्तुओं के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। अतः, यह वांछनीय होगा कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाये, जिसका मंदक प्रभाव खाद्यान्न मूल्य मुद्रास्फीति पर होगा। इसके अतिरिक्त, ताजा सब्जियों और प्रोटीनयुक्त पदार्थों, यथा, दूध, अंडे, मछली और मांस के स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

राजकोषीय परिदृश्य

राजकोषीय सुधार और राज्य स्तर पर ऋण की निरंतर प्राप्ति सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य ने 2000 के दशक के मध्य से राजकोषीय सुधार के लिए अनेक कदम उठाये हैं : वैट का कार्यान्वयन जो राज्य बिक्री कर का स्थान लेगा (अप्रैल 2005), राजकोषीय जवाबदेही कानून (मई 2006), नयी पेंशन योजना (अगस्त

सारणी 3: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई-आइडब्ल्यू) (वर्ष-दर-वर्ष)

अवधि	प्रतिशत	
	गोवा	अखिल भारत
2000-05 (5-वर्ष)	4.0	4.0
2005-10 (5-वर्ष)	9.2	7.7
2000-10 (10-वर्ष)	6.9	6.1
2010-11	12.2	10.6
2011-12 (अगस्त)	9.0	9.0

2005), गारंटियों पर अधिकतम सीमा तय करना और समेकित ऋण शोधन निधि और गारंटी प्रतिदान निधि।

घाटा और ऋण को व्यवहार्य स्तर पर बनाये रखा गया है। तथापि, अन्य राज्यों की भाँति गोवा के राज्य वित्त को वर्ष 2008-09 और 2009-10 में समष्टिआर्थिक गिरावट और छोटे वेतन आयोग पंचाटों के कार्यान्वयन के संयुक्त प्रभाव के चलते धक्का लगा। फलतः राजस्व अधिशेष में वर्ष 2008-09 में कमी आयी और वर्ष 2009-10 में वह घाटो में बदल गया। पुनः, जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात जो वर्ष 2007-08 में 2.8 प्रतिशत था, वह बढ़ कर 2009-10 तक 4.8 प्रतिशत हो गया। तथापि ऋण-जीएसडीपी-अनुपात इस अवधि में सुधरा क्योंकि ऋण में वृद्धि सांकेतिक जीएसडीपी की तुलना में कम थी (सारणी 4)।

संशोधित अनुमान के अनुसार जीएफडी-जीएसडीपी तथा ऋण-जीएसडीपी अनुपातों में राजस्व लेखा में सुधार के चलते वर्ष 2010-11 में और भी कमी आने का अनुमान है भले ही पूँजीगत परिव्यय के ऊँचा रहने का अनुमान लगाया गया है। तथापि वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान कमी दर्शाते हैं। अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि राजस्व-सृजन पर ध्यान दिया जाये ताकि राजकोषीय स्थिति की दीर्घकालिकता के लिए बढ़ते पूँजीगत और सामाजिक व्यय का वित्तपोषण किया जा सके।

सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल

गोवा का विकास-संदर्भ अन्य राज्यों से काफी अलग है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा में है और इसकी साक्षरता-दर भी सबसे ऊँची 87.4 प्रतिशत है (2011), जबकि अखिल भारतीय औसत 74.0 प्रतिशत का है (सारणी 5)। शहरी आबादी लगभग 50 प्रतिशत होने के साथ गोवा दिल्ली के बाद सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ जन्म-दर न्यून है और मृत्यु-दर न्यून

सारणी 4: राजकोषीय संकेतक

(जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	बकाया ऋण
2004-05	4.4	1.0	1.8	35.0
2005-06	4.2	0.2	1.4	35.6
2006-07	3.0	-0.9	0.4	35.5
2007-08	2.8	-0.9	0.5	34.3
2008-09	3.6	-0.5	1.4	32.0
2009-10	4.8	0.5	2.5	31.0
2010-11 (सं.अ.)	3.6	-1.1	1.5	28.7
2011-12 (ब.अ.)	4.8	0.5	2.8	...

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान ... उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: (-) घटाने का चिह्न अधिशेष को सूचित करता है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 5: गोवा के लिए मानव विकास संकेतक

मद	गोवा	अखिल भारत
आबादी (मिलियन)	1.5	1210.2
लिंग अनुपात	968	940
आबादी की वृद्धि-दर (2001-2011)	8.17	17.64
वर्ष 2009-10 में प्रति व्यक्ति आय (2004-05 की कीमत में ₹)	98,807	33,731
शिक्षा		
साक्षरता दर (पुरुष)	92.81	82.14
साक्षरता दर (महिला)	81.84	65.46
साक्षरता दर (कुल)	87.40	74.04
स्वास्थ्य*		
शिशु मृत्यु दर	10	53
सुरक्षित पेय जल तक परिवारों की पहुँच (प्रतिशत में)	82.1	90.0

*: आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11

स्रोत: जनगणना 2011 प्रारंभिक परिणाम।

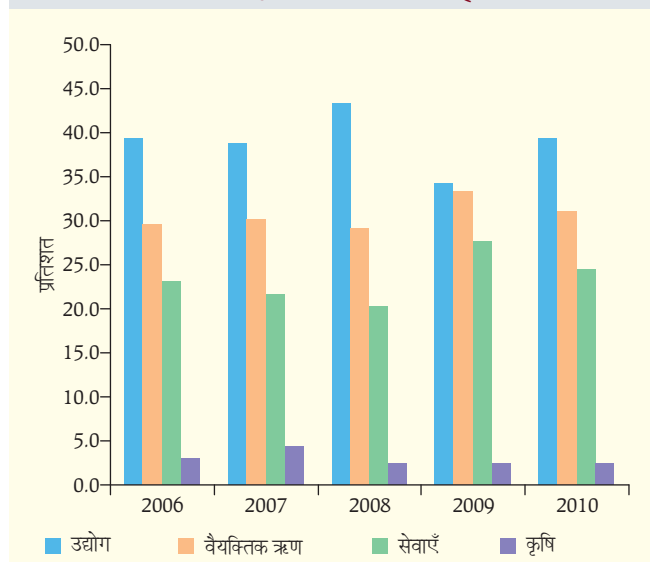
है, इसकी कुल आबादी में कार्यकारी आयु वाली आबादी का हिस्सा बड़ा है। जबकि वर्तमान आयु-प्रोफाइल द्रुत आर्थिक वृद्धि के लिए शुभ है, दीर्घावधि वृद्धि की आबादी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अतः स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्तीय क्षेत्र का विकास

कार्यकारी आयु वाली आबादी के बहुत बड़े हिस्से के संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र का विकास बचत जुटा कर और निवेश का संवर्धन करते हुए आर्थिक वृद्धि में सहायता प्रदान कर सकता है। भारत में औपचारिक वित्तीय प्रणाली में बैंकों की प्रधानता है और गोवा में भी ऐसा ही मामला है। वस्तुतः, भारत में बैंकिंग के विकास के संदर्भ में गोवा अग्रणी है। कालक्रम में गोवा में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की संख्या स्थिर गति से बढ़ी और यह वर्ष 1962 के 5 से बढ़ कर अंत-जून 2011 तक 459 हो गयी। यहाँ एक राज्य सहकारी बैंक और 7 शहरी सहकारी बैंक हैं जिनकी 136 शाखाएँ हैं। यहाँ 3,180 की आबादी पर एक वाणिज्य बैंक शाखा है, जबकि अखिल भारतीय औसत 13,270 की आबादी पर एक बैंक शाखा का है। देश में सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाओं में से एक गोवा के पास है।

ऋण का क्षेत्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था की संरचना और जनांकिकी को प्रतिबिंबित करता है। औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा ऋण में सबसे अधिक था जिसके बाद वैयक्तिक ऋण और सेवाओं का स्थान है। औद्योगिक क्षेत्र को अधिकतम ऋण प्राप्त होता है जो सतत औद्योगीकरण को प्रतिबिंबित करता है। गोवा के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल होने के चलते यहाँ आतिथ्य-क्षेत्र नीत सेवा-क्षेत्र ऋण को आकृष्ट कर रहा है, आबादी में उच्च प्रति व्यक्ति आय होने से इसकी उधार लेने की क्षमता अधिक है जो समग्र ऋण में वैयक्तिक ऋण के उच्च हिस्से से स्पष्ट है।

चार्ट 2: ऋण में व्यवसाय का हिस्सा

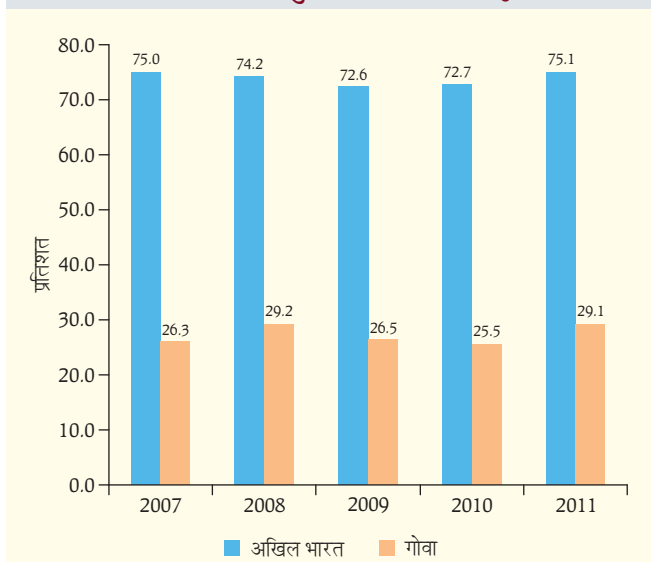


तथापि कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह कम हुआ; हालाँकि आबादी का 50 प्रतिशत अभी भी गाँवों में है (चार्ट 2)।

जबकि एनएसडीपी में कृषि का हिस्सा तेजी से घटा है, गोवा को इसके विशिष्ट कृषि उत्पादों, यथा, आम, काजू और अंगूर के लिए जाना जाता है। एक मंद पड़ता हुआ कृषि क्षेत्र दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में संतुलित वृद्धि का व्यावहारिक लक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए राज्य में कृषि का संवर्धन करने के लिए एकजुट प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि को सतत ऋण प्रवाह अपेक्षित है। राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता-प्राप्त कृषि-ऋण के लिए और कृषि उपकरणों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता के प्रावधान किये हैं। इससे राज्य में ऋण-जमा (सीडी) अनुपात के स्तर को भी बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी जो अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कम है।

राज्य का सी-डी अनुपात लगभग 30 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 75 प्रतिशत है जो इसके आर्थिक विकास के उच्च स्तर के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है (चार्ट 3)। तथापि अभिलिखित सी-डी अनुपात मुख्यतः तीन कारणों से ऋण-व्याप्ति की सीमा को कम करके बताता है। पहला, प्रमुख उद्योग यथा, फार्मास्युटिकल्स और हॉटेल अपने प्रधान कार्यालयों से ऋण प्राप्त करते हैं जो राज्य के बाहर स्थित होते हैं। अतः ऐसा ऋण-प्रवाह राज्य के सी-डी अनुपात में प्रतिबिंबित नहीं होता है। दूसरा, उद्योगों, यथा पर्यटन और लौह अयस्क में आंतरिक नकदी का सृजन किया जाना संस्थागत वित्त को घटाता है। तीसरा, अनिवासी जमाराशियों के काफी हिस्से के साथ जमा-आधार बड़ा होता है जो राज्य के सी-डी अनुपात को अधोमुखी

चार्ट 3: सीडी अनुपात की हाल की प्रवृत्ति



झुकाव देता है। यह कह कर मैं इस तथ्य को दुर्बल नहीं बना रहा कि आगे और ऋण-विस्तार गुंजाइश है, खास कर कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के क्षेत्र में।

गरीबी के न्यून विस्तार और उच्च साक्षरता के बावजूद पूरे राज्य में ऋण का असमान वितरण दिखाई पड़ता है। चूँकि स्व-रोजगार राज्य में कुल रोजगार के लगभग 32 प्रतिशत (एनएसएसओ 64वाँ दौर) के लिए जिम्मेवार है अतः ऋण की और अधिक व्यापित अपेक्षित है ताकि जनांकिकी लाभ को काम में लाया जा सके। ऋण की गैर-बराबरी पर ध्यान वित्तीय समाशन उपायों को बढ़ा कर दिया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन के उपाय

समाज में निर्धनों और कम सुविधा-प्राप्त लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने और उससे न्यायसंगत वृद्धि का सृजन कर उसे बनाये रखने के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण होता है। अब मैं वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किये गये विविध उपायों की चर्चा करूँगा।

पहला, रिजर्व बैंक ने लंबे समय से एक तंत्र संस्थित किया है जिसे 'प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार' कहते हैं, जिसके माध्यम से कुछ चुने हुए क्षेत्रों को यथा, लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय और कृषि को ऋण दिया जाता है। सुधार-पश्चात् अवधि में प्राथमिकताप्राप्त समूह का विस्तार कर उसमें खुदरा व्यापार को अग्रिम, शिक्षा-ऋण, व्यष्टि वित्त और न्यून लागत वाला आवास शामिल किया गया है। इसने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद की है।

दूसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के बजट में घोषणा की थी कि देश के ऐसे प्रत्येक गाँव में जिसकी आबादी 2000 से अधिक हो, मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी हैं। इस प्रक्रिया के परिचालन के लिए वाणिज्य बैंकों ने वित्तीय समावेशन योजनाएँ तैयार की है, जिन्हें रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत किया गया है। चूँकि बहुत छोटे केंद्रों में परंपरागत शाखाएँ खोलना व्यवहार्य नहीं होगा, दृष्टिकोण यह है कि इस चुनौती को बिजनेस करेसपॉइंट (बीसी) मॉडल के माध्यम से और संचार प्रौद्योगिकी का उन्नयन करके पूरा किया जाये। इस मॉडल के अंतर्गत बैंक एजेंटों को नियुक्त करते हैं जो ग्राहक के घर जा कर उसे बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ बैंक की ओर से प्रदान करता है।

तीसरा, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे सीमित सुविधा (नो फ़िल्ल्स) खाता खोलें। इन खातों में या तो कोई जमाशेष नहीं होता है या बहुत कम जमाशेष अपेक्षित होता है और इनमें ओवरड्राफ्ट के जरिए छोटे ऋण दिये जाने का प्रावधान होता है। यह छोटे जमाकर्ताओं के लिए बहुत सुविधाजनक खाता होता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

चौथा, किसी आम आदमी के लिए एक प्रमुख अड़चन होती है 'अपने ग्राहक को जानिये' (केवाईसी) मानदंड। छोटे खातों यथा, जिनमें 50,000 रुपये तक जमा राशि हो और 1 लाख रुपये तक ऋण दिया जाता हो, उनके लिए इस मानदंड को शिथिल किया गया है। किसी बैंक में खाता खोलने के लिए किसी मौजूदा खाताधारक द्वारा दिया गया साधारण परिचय पर्याप्त होता है। इस संबंध में केंद्र सरकार की आधार, विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) परियोजना, जिसका लक्ष्य देश में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना है, गरीब लोगों को बैंक के केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए अपनी पहचान सिद्ध करने में मदद करेगा।

पाँचवाँ, किसान बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और जनरल परपस क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के माध्यम से सुविधापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

छठा, जबकि अनेक प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं, एक आम आदमी उनसे अवगत नहीं भी हो सकता है। अतः, वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण हो जाती है। तदनुसार रिजर्व बैंक ने एक 'परियोजना वित्तीय साक्षरता' आरंभ की है जिसका उद्देश्य है केंद्रीय बैंक के बारे में सूचना का प्रसार करना और विविध लक्ष्य समूहों को सामान्य बैंकिंग अवधारणा के बारे में बताना। हमारी 'वित्तीय साक्षरता' वेबसाइट लिंक बैंकिंग, वित्त, और केंद्रीय बैंकिंग के बुनियादी तत्वों को सभी आयु-वर्ग के बच्चों के लिए प्रस्तुत करता है। हमारी वेबसाइट 13 भाषाओं में उपलब्ध है।

अंत में, रिजर्व बैंक के लिए भी सीखने की एक प्रक्रिया है। हम यह मानते हैं कि बैंकिंग के बारे में जिम्मेदार होने के नाते हमें आम आदमी की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तदनुसार, हमारे गवर्नर महोदय डॉ.सुब्बाराव, ने पिछले वर्ष हमारे प्लैटिनम जुबली समारोहों के एक भाग के रूप में आउटरीच कार्यक्रम आरंभ किया। आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत, रिजर्व बैंक का शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार के अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के अधिकारियों के साथ कम से कम एक गाँव का दौरा करता है ताकि वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह हमारे लिए जमीनी हकीकत को जानने के वास्ते बहुत समृद्ध अनुभव रहा है। तदनुसार, हमने इन कार्यक्रमों को जारी रखने का निश्चय किया है।

गोवा में वित्तीय समावेशन

अब मैं गोवा में वित्तीय समावेशन के लिए किये गये हमारे उपक्रमों के बारे में चर्चा करूँगा। पहला, ऐसे प्रत्येक गाँव में, जिसकी आबादी 2000 से अधिक है, मार्च 2012 तक एक बैंक शाखा के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए 41 गाँवों की पहचान राज्य में वित्तीय समावेशन अभियान के लिए की गयी है। 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार, 31 गाँव में बैंकिंग सेवाएँ बिजनेस करेसपॉइंट (बीसी) के माध्यम से, 4 गाँवों में मोबाइल वाहनों के माध्यम से और एक गाँव में बैंक शाखा खोल कर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की गयीं। बैंकिंग की इस व्यापकता का लक्ष्य समय से काफी पहले हासिल कर लिया गया। दूसरा, अब ध्यान उन गाँवों पर दिया जा रहा है जिनकी आबादी 1000 और 2000 के बीच है : 65 ऐसे बैंक सुविधा रहित गाँवों की पहचान की गयी है और उन्हें विभिन्न बैंकों को आवंटित किया गया है कि वे वहाँ वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करायें।

तीसरा, जून 2011 के अंत तक कुल 1,21,210 सीमित सुविधा खाते खोले गये जिनमें बकाया जमाराशि 33 करोड़ रुपये थी, इनमें से 4,930 एनएफए ऋण-सहबद्ध थे जिनमें 9.3 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी जबकि 4,763 जनरल परपस क्रेडिट कार्ड एनएफए के माध्यम से जारी किये गये जिनमें बकाया ऋण 9.3 करोड़ रुपये था। चौथा, वित्तीय शिक्षा अभियान को सुदृढ़ करने के लिए एक वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) दक्षिण गोवा के वर्ना में खोला गया। इसी प्रकार वित्तीय समावेशन अभियान को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए एक ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसडीआई) भी दक्षिण गोवा के वर्ना में खोला गया जो स्व-रोजगार के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण देता है। सफलता की कहानी के रूप में यह नोट किया जा सकता है कि इसमें 12 पाठ्यक्रम चलाये

गये और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) 230 हिताधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 55 ने लाभप्रद रोजगार कार्यकलाप आरंभ किये हैं। पांचवाँ, 71 फार्मर्स क्लबों और 20 संयुक्त दायित्व समूहों (जेएलजी) का गठन नाबार्ड द्वारा किया गया। छठा, एसएलबीसी का हाल का अभियान कि एमजीएनआरइजीए का भुगतान स्मार्ट कार्ड के माध्यम से आइटी समर्थित वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत किया जाये, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को और भी सुदृढ़ करेगा।

नीतिगत चुनौतियाँ

अब मैं व्यापक समष्टिआर्थिक नीतिगत चुनौतियों की चर्चा करूँगा। जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग के आगे विस्तार करने और वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने के लिए उपाय आरंभ किये हैं। फिर भी, गोवा की वृद्धि की गति को तेज करने के लिए आगे खड़ी कुछ चुनौतियों को मैं आलोकित करना चाहूँगा।

पहला, ऐसे प्रयास किये जाने आवश्यक हैं ताकि दीर्घकालिक औद्योगिक विकास का संवर्धन हो जो राज्य की विशिष्ट जैव-विविधता के अनुकूल हो जो बदले में स्थानीय रोजगार उत्पन्न करेगा।

दूसरा, आधारभूत संरचना में निवेश सरकारी-निजी-सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से किया जाये, ताकि उद्योग और सेवा-क्षेत्र की सहायता हो सके।

तीसरा, कृषि उत्पादकता को बढ़ाये जाने की और कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों में विविधीकरण का संवर्धन किये जाने की आवश्यकता है।

चौथा, चूँकि हाल की अवधि में खाद्य-मुद्रास्फीति प्रमुख चिंता का विषय रही है, अतः एक युक्तियुक्त आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन और राज्य स्तर पर सब्जियों और प्रोटीनयुक्त पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाना आपूर्ति-पक्ष मुद्रास्फीति के दबावों पर ध्यान देने के लिए मददगार होगा।

पाँचवाँ, राजकोषीय मोर्चे पर, सामाजिक क्षेत्र के लिए संसाधनों के आवंटन पर समझौता किये बिना राज्य के घाटों को युक्तिसंगत बनाना एक प्रमुख चुनौती होगी। अतः, एक उच्चतर वृद्धि प्रक्षेप-पथ को बनाये रखना उच्चतर राजस्व-सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि उच्च पूँजीगत परिव्यय का समर्थन किया जा सके।

छठा, साक्षरता का उच्च स्तर और मानव विकास ज्ञान-आधारित उद्योगों की आगे वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। तथापि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोवा के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सुविज्ञ कामगार बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराये। यह तकनीक और उच्च शिक्षा को सुदृढ़ किये जाने के लिए आवश्यक है।

सातवाँ, आगे और ऋण व्याप्ति की गुंजाइश है। इस संबंध में बैंक ऋणों की नवोन्मेषी संरचना की खोज कर सकते हैं, जिसमें अधिक जोर सामूहिक उधार पर और ऋण जोखिम कम करने पर दिया गया हो।

आठवाँ, वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए किसी योजना में एक बैंक शाखा का वास्तविक अस्तित्व महत्वपूर्ण होता है। अतः, सभी पणधारियों - बैंक, राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक - को निकट-समन्वय में काम करना आवश्यक है, ताकि बैंकिंग की व्याप्ति बढ़े और

प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग से बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो।

उपसंहार

अब मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। गोवा भारत का सबसे धनी राज्य है जिसमें तगड़ी संभावनाएँ हैं जैसाकि पिछले दशक के उत्तरार्ध में इसकी वृद्धि की गति में प्रतिबिंबित होता है। चुनौती यह है कि इस गति को बनाये रखा जाये जिसके लिए निरंतर नीति-संबंधी कार्रवाई और औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक अधिकाधिक पहुँच अपेक्षित होगी।